

केन्द्रीय आयोजना, 2004-2005 की विशेषताएं Highlights of Central Plan 2004-2005

ग्रामीण विकास

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

- **5100** करोड़ रुपए इस योजना के लिए प्रदान किए गए हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार तथा साथ ही खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करना है। इस प्रावधान में काम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु किया गया आबंटन शामिल है जिसका उपयोग केन्द्रित रोजगार गारंटी कार्यक्रम हेतु किया जाएगा और जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम के सम्बन्ध में दीर्घावधि वचनबद्धता प्रदान करने की दिशा में पहला कदम होगा।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

- **1000** करोड़ रुपए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए प्रदान किए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्यमों की स्थापना करने के उद्देश्य से एक संपूर्ण स्व-रोजगार कार्यक्रम है। कार्यक्रमालाप समूह और दल दृष्टिकोण इस कार्यक्रम के दो मुख्य संघटक हैं। स्वरोजगारियों में कम से कम 50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40% महिलाएं और 3% अपंग होंगे।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

- **2468** करोड़ रुपए अच्छी सर्व मौसम सड़कों के माध्यम से असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए प्रदान किए गए हैं।

ग्रामीण आवास

- **2500** करोड़ रुपए ग्रामीण निर्धनों को स्वयं उनके द्वारा निर्मित किए जाने वाले ग्रामीण आवास के लिए प्रदान किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं

- **1** करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं हेतु प्रावधान के लिए सांकेतिक आबंटन किया गया है।

पेय जलापूर्ति

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

- **2900** करोड़ रुपए राज्यों को सभी ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेय जल प्रदान करने के उनके प्रयास को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए गए हैं।

ग्रामीण सफाई

- **400** करोड़ रुपए ग्रामीण सफाई के लिए प्रदान किए गए हैं, जो राज्यों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले चयनित जिलों में संपूर्ण सफाई अभियान के लिए हैं।

भू-संसाधन

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

- **448** करोड़ रुपए जनता की भागीदारी के माध्यम से जलसंभर आधार पर विकास के लिए प्रारंभ किए जाने वाले अतिरिक्त 10 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए प्रदान किए गए हैं।

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

- **300** करोड़ रुपए लगभग 12 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए प्रदान किए गए हैं।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

- **215** करोड़ रुपए 8.50 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना

- **200** करोड़ रुपए जल संरक्षण हेतु प्रदान किए गए।

कृषि और सहकारिता

- **350** करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए प्रदान किए गए हैं।
- **719.94** करोड़ रुपए कृषि में वृहद प्रबंधन के लिए प्रदान किए गए हैं।
- **200** करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल में बागवानी में प्रौद्योगिकी मिशन के लिए प्रदान किए गए हैं।

उर्वरक

- **117.09** लाख टन नाइट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- **49.23** लाख टन फास्फेटी उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

कोयला तथा लिग्नाइट

- **404.19** मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- **21** मिलियन टन लिग्नाइट के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता

- **3057** करोड़ रुपए सर्व-शिक्षा अभियान के लिए प्रदान किए गए हैं। इसका उद्देश्य एक मिशन के रूप में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का कार्यान्वयन करना है, जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को उत्तम प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों, शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले तथा निम्न महिला साक्षरता वाले ब्लाकों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **1675** करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा के समर्थन में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम हेतु प्रदान किए गए हैं।
- **250** करोड़ रुपए प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रदान किए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

- **750** करोड़ रुपए सूचना प्रौद्योगिकी के विकास तथा संवर्धन के लिए प्रदान किए गए हैं।

RURAL DEVELOPMENT

Sampoorna Gramin Rozgar Yojana

- **5100** crore rupees provided for the scheme. The objective of the scheme is to provide additional wage employment in rural areas as also food security. The provision includes allocation for the Food for work Programme, which will be utilised for a focused employment guarantee programme - a first step towards the long term commitment to an employment guarantee programme.

Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana

- **1000** crore rupees provided for the scheme which is a holistic self-employment programme with the objective of establishing a large number of micro-enterprises in rural areas. Activity clusters and group approach are the two key components of the programme. At least 50% of the swarozgaris will be SCs/STs, 40% women and 3% disabled.

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

- **2468** crore rupees provided for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana with the objective of providing connectivity to unconnected rural habitations through good all weather roads.

Rural Housing

- **2500** crore rupees provided for rural housing for rural poor to be built by themselves.

Urban amenities in Rural Areas

- **1** crore rupees. Token allocation made for "Provision for Urban amenities in Rural Areas (PURA)".

DRINKING WATER SUPPLY

Accelerated Rural Water Supply Programme

- **2900** crore rupees provided to supplement the States in their effort to provide safe drinking water to all rural habitations.

Rural Sanitation

- **400** crore rupees provided for rural sanitation is for Total Sanitation Campaign in selected districts to be decided by the States.

LAND RESOURCES

Integrated Wastelands Development Programme

- **448** crore rupees provided for additional 10 lakh hectares to be taken up for development on watershed basis through people's participation.

Drought Prone Areas Programme

- **300** crore rupees provided for additional areas covering about 12 lakh hectares.

Desert Development Programme

- **215** crore rupees provided for an additional area covering 8.50 lakh hectares.

Pradhan Mantri Gramin Jal Samvardhan Yojana

- **200** crore rupees provided for Water Conservation.

AGRICULTURE AND COOPERATION

- **350** crore rupees provided for Crop Insurance Scheme.
- **719.94** crore rupees provided for Macro-management in agriculture.
- **200** crore rupees provided for Technology Mission in Horticulture in North Eastern Region, Jammu & Kashmir and Uttaranchal.

FERTILIZERS

- **117.09** lakh tonnes of Nitrogenous fertilizer production targeted.
- **49.23** lakh tonnes of phosphatic fertilizer production targeted.

COAL AND LIGNITE

- **404.19** million tonnes of coal production targeted.
- **21** million tonnes of lignite production targeted.

ELEMENTARY EDUCATION AND LITERACY

- **3057** crore rupees provided for Sarva Shiksha Abhiyan. It is meant for implementation of universal elementary education in a mission mode with a clear district focus to provide quality elementary education to children of the age group of 6-14 years. Special focus will be on girls, children belonging to SC/ST communities, urban slum dwellers and low female literacy blocks.
- **1675** crore rupees provided for national programme of Nutritional Support to Primary Education.
- **250** crore rupees provided for Adult Education.

INFORMATION TECHNOLOGY

- **750** crore rupees provided for the development and promotion of Information Technology.

स्वास्थ्य

- 269 करोड़ रुपए राष्ट्रीय रोगवाही जनित रुग्णता कार्यक्रम, जिसमें कालाजार जापानी मस्तिष्क ज्वर, फिलेरिया और डेंगु शामिल हैं, के लिए प्रदान किए गए हैं।
- 232 करोड़ रुपए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए हैं।
- 125 करोड़ रुपए क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए हैं।
- 88 करोड़ रुपए अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए हैं।
- 60 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए हैं।
- 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एआईआईएमएस की तरह के 6 अस्पताल-सह-अध्यापन केंद्रों की स्थापना और राज्य सरकारों के अस्पतालों के उन्नयन हेतु की गई है।

योजना

- 6000 करोड़ रुपए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की नई/पुनः संरचित योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। ये योजनाएं राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों में सहायक होंगी।

रेलवे

- 20000 वैगन, 2214 कोच, 332 ईएमयू, 120 डीजल लोको तथा 90 इलैक्ट्रिक लोको का निर्माण किया जाएगा।
- 4125 किलोमीटर ट्रैक का नवीकरण किया जाएगा।
- 375 रूट किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया जाएगा।
- 1000 रूट किलोमीटर मार्ग का गेज परिवर्तन किया जाएगा
- 273 किलोमीटर नई लाइनें बनाई जाएंगी।

दूरसंचार

- 105 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों की संस्थापना बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा की जाएगी।

कृषि और ग्रामीण उद्योग

- 200 करोड़ रुपए की शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना में व्यवस्था की गई है।
- 248 करोड़ रुपए की व्यवस्था खादी और ग्रामोद्योग के विकास के माध्यम से ग्रामीण उद्योग/क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम हेतु की गई है।
- 100 करोड़ रुपए पारंपरिक उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु निधि के लिए प्रदान किए गए हैं।

लघु उद्योग

- 176 करोड़ रुपए की व्यवस्था लघु उद्योग क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि हेतु की गई है।

इस्पात

- 18.02 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य एसएआईएल, आरआईएनएल और टीआईएससीओ द्वारा रखा गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

- 313.24 करोड़ रुपए वर्ष 2004-05 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्तियों की व्यवस्था के लिए जिसके द्वारा लगभग 20.80 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है।
- 402 करोड़ रुपए की व्यवस्था वर्ष 2004-05 के दौरान विशेष संघटक आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता जिसके द्वारा लगभग 4.50 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत

- 4250 गांवों और बस्तियों को विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
- 525 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता नवीकरणों से बढ़ाई जाएगी।

जनजातीय मामले

- 497 करोड़ रुपए की व्यवस्था अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लाभ के लिए जनजातीय उप-आयोजना क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई है।
- 330 करोड़ रुपए की व्यवस्था जनजातीय क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए इनमें महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे के सृजन हेतु की गई है।
- 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था वर्ष 2004-05 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्तियां देने के लिए जिसके द्वारा लगभग 5 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- 241 करोड़ रुपए की व्यवस्था विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (एस ई आर सी) के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में बहुविध अनुसंधान के लिए की गई है।

अन्तरिक्ष

- 490 करोड़ रुपए की व्यवस्था भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (जीएसएलवी) मार्क-III के विकास के लिए की गई है।
- 430 करोड़ रुपए की व्यवस्था इन्सैट आपरेशन के लिए की गई है।
- 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था रडार इमेजिंग सेटेलाइट-1 (आरआईएसएटी-1) के लिए की गई है।
- 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारतीय चन्द्रमा मिशन - चन्द्रायान-1 के लिए की गई है।

खेल

- 123.83 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए की गई है।

विद्युत

- 566590 मिलियन यूनिटों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

website: <http://indiabudget.nic.in>

HEALTH

- 269 crore rupees provided for National Vector Borne Disease programme, including Kala-Azar, Japanese Encephalitis, Filaria and Dengue.
- 232 crore rupees provided for National AIDS Control Programme.
- 125 crore rupees provided for Tuberculosis Control Programme.
- 88 crore rupees provided for Blindness Control Programme.
- 60 crore rupees provided for National Cancer Control Programme.
- 60 crore rupees provided for establishment of 6 AIIMS-type Hospitals-cum-teaching centres and upgradation of State Government Hospitals under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.

PLANNING

- 6000 crore rupees provided for new/restructured schemes of the Central Ministries/Departments. These schemes will subserve the objectives of the National Common Minimum Programme.

RAILWAYS

- 20000 wagons, 2214 coaches, 332 EMUs, 120 Diesel locos and 90 Electric locos to be added.
- 4125 kilometers of track renewal.
- 375 route kilometers of electrification.
- 1000 route kilometers of gauge conversion.
- 273 kilometers new lines to be added.

TELECOMMUNICATIONS

- 105 lakh direct exchange lines to be installed by BSNL & MTNL.

AGRO AND RURAL INDUSTRIES

- 200 crore rupees provided for Prime Minister's Rozgar Yojana to assist educated unemployed youth.
- 248 crore rupees provided for Rural Employment Generation Programme to generate additional employment in the rural industries/sector through development of Khadi and Village Industries.
- 100 crore rupees provided for fund for modernisation of traditional industries.

SMALL SCALE INDUSTRIES

- 176 crore rupees provided for Credit Guarantee Fund for SSI to provide collateral free loan to SSI Sector.

STEEL

- 18.02 million tonnes of production of saleable steel by SAIL, RINL and TISCO targeted.

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

- 313.24 crore rupees provided for Post Matric Scholarships for SC students by which about 20.80 lakh students are likely to benefit during 2004-2005.
- 402 crore rupees provided towards Special Central Assistance for Special Component Plan by which about 4.50 lakh Scheduled Caste families are likely to benefit during 2004-2005.

NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

- 4250 villages and hamlets proposed to be electrified.
- 525 MW power generation capacity to be added from renewables.

TRIBAL AFFAIRS

- 497 crore rupees provided towards Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan Areas for the benefit of Scheduled Tribe families.
- 330 crore rupees provided for creating critical infrastructure in the Tribal Areas to bring them at par with developed areas.
- 65 crore rupees provided for Post Matric Scholarships for Scheduled Tribe students by which about 5 lakh students are likely to be benefited during 2004-05.

SCIENCE AND TECHNOLOGY

- 241 crore rupees provided for Multi Disciplinary Research in Science and Technology Programme under the Science and Engineering Research Council (SERC).

SPACE

- 490 crore rupees provided for Geo-synchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mark-III Development.
- 430 crore rupees provided for INSAT operation.
- 125 crore rupees provided for Radar Imaging Satellite-1 (RISAT-1).
- 70 crore rupees provided for Indian Lunar Mission - Chandrayaan -1.

SPORTS

- 123.83 crore rupees provided for Sports Authority of India.

POWER

- 566590 million units generation targeted.